हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 18 मार्च 2026, समय 1305 (5 मिनट)

हरियाणा सरकार राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक 'ग्रीन हाइड्रोजन नीति' पेश करने जा रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह जानकारी दी। जिस में भारत के पहले प्रति वर्ष 10,000 टन क्षमता वाले मेगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की गई। यह परियोजना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल के तहत पानीपत में स्थापित की जा रही है।

मुख्य सचिव ने बताया कि यह संयंत्र भारतीय तेल निगम की पानीपत रिफाइनरी को ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा और इसे दिसंबर 2026 तक क्रियाशील करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और प्रधानमंत्री की 'पंचामृत' प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि 'राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' के तहत शुरू की गई इस पहल से, हरियाणा में 250 KTPA की क्षमता हासिल होने पर, विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के लगभग 40,000 प्रत्यक्ष और एक लाख 20 हजार अप्रत्यक्ष अवसर पैदा हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना से राज्य के कुल घरेलू उत्पाद में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलने की संभावना है, और यह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उस परिकल्पना को भी मज़बूती देगा, जिसके तहत हरियाणा में एक सुदृढ़ ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाना है।

****

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट का लक्ष्य वर्ष 2047 से पहले हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाना है।मुख्यमंत्री बजट पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने विपक्ष द्वारा बजट को शब्दों और आंकड़ों का मकड़जाल बताने पर कहा कि सरकार ने वर्ष 2047 तक एक विकसित हरियाणा की परिकल्पना की है। इसलिए हमारे सभी बजट प्रावधान केवल तात्कालिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि हरियाणा की आने वाली पीढ़ियों के सशक्त व सुनहरे भविष्य के लिए हैं।

उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता चौपालों का महत्व और रास्तों को भूल गये हैं इसलिए उनके रखरखाव के लिए पंचायतों को पैसे देने के उनके ऐतिहासिक प्रस्ताव पर आपत्ति कर रहे हैं।मुख्यमंत्री ने विपक्षियों द्वारा प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने के संबंध में लगाए गए आरोपों पर कहा कि बजट में कुल 15 बार नौकरी व रोजगार शब्द का उपयोग हुआ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी नेता ने सी.एम.आई.ई. रिपोर्ट का जो आंकड़ा बताया है, ऐसा कोई आंकड़ा संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध ही नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के "सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय" द्वारा अक्तूबर से दिसम्बर 2025 तक की अवधि के करवाये गये नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार संपूर्ण हरियाणा में बेरोजगारी दर 5.0 प्रतिशत बताई गई है जो कि पड़ोसी राज्यों पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की तुलना में काफी कम है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बेरोजगारी की दर 7.2 प्रतिशत, पंजाब में 7 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी हटाने के ठोस प्रयास किए हैं। वर्ष 2014 से अब तक 1 लाख 72 हजार 774 युवाओं को योग्यता के आधार सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्षी नेताओं के दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के बजट को कम होने संबंधी आरोपों पर कहा कि विपक्षियों के अनुसार प्रदेश में 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं की संख्या 82 लाख 50 हजार है। इनके लिए 2,100 रुपये प्रति माह दिया जाए, तो बजट लगभग सालाना 20 हजार करोड़ रुपये बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना लाडो लक्ष्मी योजना के भी 18 से 60 वर्ष आयु की 34 लाख 27 हजार 993 महिलाएं 3200 रुपये सहायता या तो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता या विधवा पेंशन या अविवाहित पेंशन या दिव्यांग इत्यादि ले रही हैं। वे 3200 रुपये का लाभ नहीं छोड़ेंगी? इन 34 लाख महिलाओं के लिए विपक्षी नेता बजट प्रावधान क्यों चाहते हैं ?उन्होंने कहा कि सरकार की गारंटी है कि 6 हजार 500 करोड़ रुपये का किया गया प्रावधान यदि कम पड़ जाएगा तो पूरक बजट में जितनी भी जरूरत होगी, वह पूरी कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अपराध को लेकर आरोपों को केवल अधूरी जानकारी प्रस्तुत करके प्रदेश की छवि को धूमिल करने का प्रयास बताया । उन्होंने कहा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, वे केवल वार्षिक अपराधों की संख्या से संबंधित होते हैं। ब्युरो कहीं भी यह नहीं बताता कि कोई राज्य 'सबसे खतरनाक' है या 'सबसे सुरक्षित'। इसलिए यह कहना कि हरियाणा देश के 10 सबसे खतरनाक राज्यों में शामिल है, पूरी तरह भ्रामक और अनुचित है।उन्होंने कहा कि आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि पिछले वर्षों में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

****

****

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि फ़िरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तावडू में एक नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कल बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि जिला नूंह में दो सरकारी नशा मुक्ति केन्द्र कार्यरत हैं। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज , नल्हड़ में 10 तथा जिला नागरिक अस्पताल मांडीखेड़ा में 17 बेड नशा मुक्ति के लिए आने वाले मरीजों के लिए आरक्षित हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 से अब तक जिला नूंह में नशे के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

****

****